महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को किया निलंबित

रायपुर,(**आरएनएस**)। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने शनिवार को लोक सुराज अभियान के तहत गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड के ग्राम माड़ागांव प्रवास पर थे। यहां आयोजित समाधान शिविर में मुख्यमंत्री को कृषकों द्वारा बीज मिनीकिट वितरण नहीं किये जाने को लेकर मिली शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी व प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी ललित कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया है।

16 आईपीएस अफसरों की वरिष्ठता बदली

2008, 2009, 2010 व 2011 बैच के हैं सभी आईपीएस

आरएस नायक अब आईजी से होंगे रिटायर

रायपुर,(**आरएनएस**)। सूबे के चार बैच के सोलह आईपीएस अफसरों को सीनियरटी का बड़ा तोहफा मिल गया है। ये सभी प्रमोटी आईपीएस हैं, प्रदेश में ऐसे सोलह आईपीएस हैं जिनकी सीनियरटी बदली है। पंजाब हाइकोर्ट के आदेश के बाद पूरे भारत में प्रमोटी अधिकारियों की वरीयता सूची में परिवर्तन हो रहा है, इसके पहले सूबे के आईएएस अवार्ड अधिकारियों का प्रमोट ईयर बदल गया था। अबकि प्रमोटी आईपीएस की लिस्ट आई है जिसके अनुसार एएम जूरी 2000 बैच अब 1999, पी के दास 2000 बैच अब 2000, के सी अग्रवाल 2001 बैच अब 2001, केके अग्रवाल 2001 बैच अब 2001, एसएस सोरी 2003 बैच अब 2002 , टीआर पैकरा 2003 बैच अब 2002, डी एल मनहर 2004 बैच अब 2003, आरएस नायक 2004 बैच अब 2003, जी एस दर्रो 2004 बैच अब 2003, नरेंद्र खरे 2004 बैच अब 2003, सुशील चंद्र द्विवेदी 2004 बैच अब 2003, जेएस वट्टी 2004 बैच अब 2003, अकबर राम कोर्राम 2004 बैच अब 2003, आरपी साय 2004 बैच अब 2003, डॉ संजीव शुक्ला 2005 बैच अब 2004, हेतराम मनहर 2005 बैच से अब 2004 बैच के माने जाएँगे। इस सुची में पी के दास, केसी अग्रवाल और केके अग्रवाल का बैच परिवर्तन नहीं हुआ है। बहरहाल इस बैच परिवर्तन से सीधा फ़ायदा आरएस नायक का हुआ है। आरएस नायक की क़िस्मत को छक्का कुछ ऐसा लगा है कि अब वे आईजी पद से रिटायर होंगे।

पार्षद के खिलाफ अवैध कब्जा कर प्रताड़ित करने का आरोप

कोरबा (**आरएनएस**)। नगर निगम के परसाभाठा वार्ड के पार्षद संतोष कुर्रे के खिलाफ बस्ती के ही निवासी वृद्ध सनतराम खरे ने उसकी जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एएसपी से शिकायत की है। वृद्ध के मुताबिक 20 वर्षो से जिस जमीन पर उसका कब्जा है, उसमें कुछ माह पूर्व पार्षद कुर्रे ने बेजा कब्जा किया। पार्षद के कांग्रेस से जुड़े व प्रभावशाली होने के कारण उसने शिकायत नहीं किया। लेकिन अब वह बची हुई जमीन पर भी बेजा कब्जा कर रहा है। मना करने पर वह झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज देने की धमकी देता है। एएसपी कीर्तन राठौर ने वृद्ध को शिकायत पर जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

एएसआई बनने के लिए प्रधानआरक्षक ने लगाई दौड़, गिरने से हुई मौत

भिलाई ,(**आरएनएस**)। भिलाई शहर में आज सुबह पुलिस महकमें में उस वक्त शोक की लहर फैल गई जब वहां के एक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक की आकस्मिक गिरकर मृत्यु हो गई। घटना भिलाई के सेक्टर-7 सेंट्रल एवेन्यू की है, जहां आज पुलिस विभाग की इंटर डिपार्टमेंटल परीक्षा चल रही थी। फिजिकल परीक्षा के दौरान ही हेड कांस्टेबल घनश्याम पटेल की मौत हो गयी। मिली जानकारी के मुताबिक आज पुलिस विभाग की अंतर विभागीय परीक्षा हो रही थी, जिसे पास कर हेड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक में प्रमोशन होना था। फिजिकल परीक्षा भिलाई के सेक्टर-7 स्थित सेंट्रल एवेन्यू में चल रही थी। 5 किलोमीटर की दौड़ की प्रतियोगितिया के दौरान कुछ दूर दौड़ने के बाद घनश्याम पटेल सीधे जमीन पर गिर गये। इस दौरान आसपास मौजूद प्रतिभागियों ने तत्काल उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुके थे, उनकी सांसे काफी लंबी चल रही थी, जहां उन्हें सेक्टर-9 के अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डाक्टरों ने हेड कांस्टेबल के हार्ट अटैक की आशंका जतायी है। जानकारी के मुताबिक घनश्याम पटेल सुपेला थाना में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे। जो पुलिस विभाग द्वारा प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक आ वर्ग की फिजिकल परीक्षा में शामिल हो रहे थे। परीक्षा की शुरुआत 5 किलोमीटर दौड़ कराई जा रही थी। सुपेला थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक का बैच नंबर 679 था।

कार में रखे लेपटाप व मशीन पार

रायपुर,(**आरएनएस**)। शकरनगर सेक्टर 1 के पास खड़ी कार का दरवाजा खोलकर अज्ञात चोर ने लेपटाप व फेफड़ा जांच करने का मशीन पार कर दिया। प्रार्थी की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी डॉ. तुसार पुखराज जैन पिता पुखराज जैन 34 वर्ष एलआईजी 31 सेक्टर 1 शंकरनगर का रहने वाला है। बताया जाता है कि 15 मार्च के शाम प्रार्थी अपनी कार को घर के सामने खड़ी किया था तभी अज्ञात चोर ने कार का दरवाजा खोलकर सीट पर रखे लेपटाप व फेफड़ा जांच करने का मशीन पार कर दिया। चोरी गए जुमला कीमती करीब 60 हजार रूपए के आसपास बताई जा रही है।

राशन कार्ड के लिए 'आधार' फिलहाल अनिवार्य नहीं- डॉ. रमन सिंह

रायपुर,(**आरएनएस**)। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राशन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड फिलहाल अनिवार्य नहीं है। अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों के आधार पर भी राशन कार्ड जारी किए जा सकते है। डॉ. सिंह आज लोक सुराज अभियान के तहत दिनभर प्रदेश के तीन जिलों-धमतरी, गरियाबंद और दुर्ग के तीन गांवों का हेलीकाप्टर से सघन दौरा करने के बाद देर शाम जिला मुख्यालय राजनांदगांव कलेक्टोरेट में दो जिलों-राजनांदगांव और कबीरधाम (कवर्धा) के अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ले रहे थे। डॉ. सिंह ने बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रदेश भर में यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि पटवारी हल्कों के स्तर पर आवेदकों के नामांतरण, बटवारा और सीमांकन जैसे लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निपटारा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत प्रदेश में लगभग 6 लाख 80 हजार घरों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए चालू माह मार्च से जून तक लगभग साढ़े तीन माह का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सौभाग्य योजना में लगभग 18 से 20 हजार मजरों-टोलों में भी बिजली पहुंचाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विद्युतीकरण के इस लक्ष्य को हर हाल में निर्धारित समय-सीमा में जून कर लिया जाए ताकि बारिश के दिनों में भी इन घरों और बसाहटों को बिजली की कोई समस्या न हों। डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों में भी बिजली की समुचित व्यवस्था करने का आदेश दिया। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 में अब तक लगभग दो साल में 22 हजार 500 मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जो कुल स्वीकृत मकानों का 81 प्रतिशत है। इसी तरह कबीरधाम (कवर्धा) जिले में इस अवधि में 15 हजार 784 परिवारों के मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया हैं। लोक सुराज अभियान की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव जिले में इस बार के अभियान के प्रथम चरण में आयोजित आवेदन संकलन शिविरों में 3 लाख 06 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। अभियान के दूसरे चरण में इनमें से 2 लाख 94 हजार आवेदनों का निराकरण कर दिया गया। इस प्रकार निराकरण लगभग 96 प्रतिशत रहा। अभियान के दौरान राजनांदगांव जिले में अब तक 21 हजार 690 नए राशन कार्ड बनवाए गये। इनमें से 1261 राशन कार्ड विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के परिवारों को जारी किए गये। सीमांकन, बटवारा एवं नामांतरण के 3469 आवेदनों का निपटारा किया गया। उन्होंने कहा कि मेहनतकश मजदूरों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आगामी अप्रैल एवं मई के महीने में प्रदेश के कबीरधाम और राजनांदगांव जिलों में दो विशाल शिविर लगाए जाएंगे। डॉ. सिंह ने अधिकारियों को इन शिविरों की तैयारी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत हुए निर्माण कार्यों में दोनों जिलों में कुछ श्रमिकों की बकाया मजदूरों का भुगतान नहीं होने की जानकारी मिली है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत हितग्राहियों द्वारा निर्मित शौचालयों की राशि बकाया होने के कुछ प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने दोनों जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इन प्रकरणों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी पंचायत विभाग और अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर गर्मियों में गांवों और शहरों में पेयजल की नियमित आपूर्ति बनाए रखें। स्वास्थ्य विभाग गर्मी के मौसम में संभावित संक्रामक बीमारियों से बचाव के अग्रिम उपाय सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित केन्द्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की विशेष रूप से समीक्षा की।

ब्लैकमेल के आरोपियों को अग्रिम जमानत

कोरबा(**आरएनएस**)। शहर के सांईकृपा हॉस्पिटल की संचालिका डॉ. गुलशन व उनके पति डॉ. प्रेमीश वर्मा को अवैध गर्भपात का स्टिंग बताकर ब्लैकमेल करते हुए 2 लाख रुपए वसूलने के मामले में दो आरोपी एस बी द्विवेदी व अनुप अग्रवाल को एडीजे कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई। द्विवेदी रायपुर व अग्रवाल दिल्ली निवासी है। न्यायालीयन सूत्रों के मुताबिक आरोपियों की ओर से वकील ने कोर्ट में डॉण् दंपती से विज्ञापन लेकर संबंधित न्यूज चैनल पर चलाने का दस्तावेज पेश किया। वहीं मामले में डॉक्टर दंपती पर झूठा फ ंसाने का जिक्र किया। वहीं देरी से रिपोर्ट करने को भी आधार बताया गया। जिस पर कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत स्वीकार कर ली। इस मामले में खुद को पत्रकार बताने वाले उत्तराखंड व पंजाब के रहने वाले एक महिला व एक पुरुष अभी फरार हैं। कोरबा पुलिस ने करनाल में पकड़े गए अवैध गर्भपात की स्टिंग का भय दिखाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का डिटेल मांगी है।

बस व कार भिडंत, गुस्साए ग्रामीणों ने बस को किया आग के हवाले

पत्थलगांव,(**आरएनएस**)। रविवार सुबह बस और कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस घटना में सामने बैठे दो लोगों को अधिक चोटें आई है, कार के पीछे बैठे तीन अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है। टक्कर के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। घटने के बाद घायलों को पत्थलगांव के सिविल अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया है जहां इनका इलाज जारी है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार भाटामुड़ा निवासी सरमित सिंह अपने परिजनों के साथ रविवार की सुबह कार मारुति 800 (सीजी 14-सी 0586) से रायगढ़ जा रहे थे। तभी ग्राम बगुडेगा के समीप कार को सामने से आ रही रायगढ़ से अम्बिकापुर चलने वाली दुर्गा बस ने सामने से टक्कर मार दी। इससे कार चालक सरमित के सिर एवम् सीने में गहरी चोंटे आई है, वहीं सामने बैठे एक अन्य व्यक्ति को भी सीने में ही चोट लगी है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बस को आग के हवाले कर दिया। घटना कर बाद बस के चालक एवम् क्लीनर मौके से फरार बताये जा रहे है।

खूटपदर गोलीकांड, गैदू को मिली राहत, सुको से हुई जमानत

जगदलपुर,(**आरएनएस**)। 11 मई 2017 को खूटपदर में हुए गोलीकांड में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के प्रदेश सचिव और बस्तर परिवहन संघ के अध्यक्ष रहे मलकीत सिंह गैदू की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बार के स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुको की डबल बेंच के जस्टिस एसए बोदरे और जस्टिस नागेश्वर राव ने यह फैसला सुनाया है। सुको के सीनियर एडवोकेट केटीएस तुलसी ने गैदू की ओर से पैरवी की। बीते महीने हाईकोर्ट ने गैदू को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद वे सुको पहुंचे। इस निर्णय के साथ ही यह भी कहा गया है कि गैदू अब निचली अदालत में रेगुलर बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि मामले में आरोपी बनाए गए कई लोग अब भी फरारी काट रहे हैं।

जंगल में कराया सुरक्षित प्रसव

कोरबा(**आरएनएस**)। जिले की ग्राम पंचायत मदनपुर के आश्रित ग्राम सरडीह की शांतिबाई 28 को शनिवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई। सूचना पर पौने 9 बजे महतारी एक्सप्रेस करतला से निकली, लेकिन बीहड़ व रास्ता नहीं होने के कारण वह गांव तक नहीं पहुंच पाई। टीम के सदस्य ई एम टी त्रिभुवन प्रजापति, कैप्टन नीरजकुमार मिश्रा, ई एम ई मिथिलेश चौहान व मितानिन रातियानो पैदल सरडीह पहुंचे। गर्भवती को जंगल के रास्ते नाव से नदी पार कराकर वाहन तक लाए। इसके पहले कि वे अस्पताल पहुंचते, दर्द बढ़ गया तो जंगल में ही सुरक्षित प्रसव कराया। शांति देवी ने स्वस्थ बालक को जन्म दिया।

सहारा के जमाकर्ता अपनी ही राशि वापस पाने दर-दर भटक रहे

जरूरतमंदों को सहारा से ही नहीं मिल रहा सहारा

जगदलपुर,(**आरएनएस**)। पिछले लंबे समय से अपनी ख्याति तथा परिपक्वता अवधि के पश्चात तुरंत ही लाखों रूपये भुगतान प्रदान करने वाली सहारा फायनेंस कंपनी से ही अब लोगों को सहारा नहीं मिल पा रहा है। ग्राहकों द्वारा इस संबंध में बताया गया कि लाखों रूपये की राशि उन्होंने जरूरत के समय प्राप्त करने के लिए छोटी-छोटी सहारा की योजनाओं के माध्यम से प्रतिदिन जमा की और परिपक्वता के पश्चात भुगतान लेने का जब समय आया तो सहारा द्वारा मात्र कुछ हजार रूपयों की राशि ही प्रदान करने की बात की जाती है और लाखों रूपयों के भुगतान के लिए उन्हें माह दर माह सहित वर्षो तक घुमाया जाता है। इस प्रकार उन्हें जरूरत के समय अपनी ही जमा राशि नहीं मिल पा रही हैं। उल्लेखनीय है कि सहारा वित्त कंपनियों ने हजारों ग्राहकों ने कंपनी की दैनिक जमा योजना सहित अनेक जमा करने की योजनाओं प्रतिदिन के हिसाब से राशि जमा की और पूर्व के वर्षो में परिपक्वता के पश्चात उन्हें भुगतान माह डेढ़ माह की अवधि के पश्चात प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब से सहारा प्रमुख पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी तब से उनका भुगतान हमेशा से चल रही प्रक्रिया के अनुसार नहीं चला और उन्हें अपनी ही राशि के लिए चक्कर पर चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कंपनी के द्वारा कुछ वित्तीय गड़बड़ियां किये जाने से बैंक खाते फ्रीज कर दिये गये हैं। जिसके कारण सहारा इन खातों से रकम नहीं निकाल पा रही हैं और इसके कारण जनता को दिया जाने वाला भुगतान भी नहीं हो पा रहा है। मात्र बीस हजार रूपये तक की राशि का भुगतान स्थानीय स्तर पर किया जाता है और लाखों रूपयों की जमा राशि के बारें में स्थानीय सहारा कार्यालय के द्वारा कहा जाता है कि हेड ऑफिस को भुगतान के लिए संबंधित प्रपत्र भेजे गये थे। वहां से जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हुई तब भुगतान किया जायेगा। यह स्वीकृति ही आजकल एक डेढ़ माह के स्थान पर वर्षो तक नहीं मिल पा रही है। ग्राहकों ने इस संबंध में प्रशासन ने आग्रह किया है कि वह इस मामलें में हस्तक्षेप कर ग्राहकों की भुगतान राशि प्रदान करवाने का कार्य करें।

परिवहन व्यवसायी ने मांगी सपरिवार आत्महत्या की अनुमति

मैंने मुख्यमंत्री से अपनी समस्या के निराकरण की मांग की है। समस्या का समाधान नहीं होने पर सपरिवार आत्महत्या करूंगा। मेरे और मेरे परिवार की मौत के लिए संबंधित अधिकारी और राज्य शासन जिम्मेदार होगा। -- बृजेश त्रिपाठी

कोरबा (**आरएनएस**)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह इन दिनों प्रदेश भर में सुराज अभियान चला रहे हैं। लेकिन हकीकत को धरती पर सुराज का दावा खरा उतरता नजर नहीं आता। इसका जीता-जागता उदाहरण कोरबा का परिवहन व्यवसायी बृजेश त्रिपाठी है। अपनी समस्या को लेकर आवेदन पर आवेदन देकर थक चुके बृजेश त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री से सपरिवार आत्महत्या की अनुमति मांगी है। परिवहन व्यवसायी बृजेश त्रिपाठी लगभग दो दशक से यात्री बसों का संचालन करते रहे हैं। पत्नी, एक पुत्र और दो पुत्रियां का उनका छोटा सा परिवार है। बृजेश त्रिपाठी की दुश्वारियां दो वर्ष पूर्व तक शुरू हुई, जब छत्तीसगढ़ शासन ने जन सुविधा के लिए सिटी बस संचालन की योजना बनायी। कोरबा में भी कोरबा अरबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सोसायटी बनाकर सिटी बस का संचालन प्रारंभ किया गया। सिटी बस संचालन का ठेका दुरगम्बा ट्रासपोर्ट नामक एक निजी कंपनी को दिया गया। निजी ठेका कंपनी ने कोरबा-मड़वारानी-चांपा मार्ग पर परमिट के लिए आवेदन किया। चूंकि इस मार्ग पर कोई भी समय अंतराल उपलब्ध नहीं था, निजी बसों का पूरे समय संचालन हो रहा था। लिहाजा निजी बस संचालकों ने आपत्ति दर्ज करायी। लेकिन परिवहन विभाग ने उनकी सुनवाई नहीं की। बल्कि निजी बसों के समय पर सिटी बसों के लिए समानान्तर परमिट जारी कर दिया गया। बृजेश त्रिपाठी के अनुसार इसके बाद सिटी बस ठेकेदार ने निजी बसों के आगे-आगे बल पूर्वक सिटी बस का संचालन शुरू कर दिया। नतीजतन निजी बसें एक-एक कर बंद होने लगी। सिटी बस संचालक ठेकेदार की गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायतों को प्रशासन ने हमेशा अनसुना कर दिया। बृजेश त्रिपाठी की तेरह (13) यात्री बसें बंद हो गयीं। अब बृजेश त्रिपाठी के सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या पैदा हो गयी है। परिवहन अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक की गयी शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बृजेश त्रिपाठी अब पूरी तरह निराश और हताश हो चुके हैं। उन्होंने 14 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री के नाम आवेदन सौंप कर पन्द्रह दिवस में अपनी समस्या का निराकरण करने अथवा पत्नी, पुत्र और दो पुत्रियों सहित आत्महत्या करने की अनुमति देने की मांग की है।

माईंस प्रोटेक्टेड व्हीकल से अभी तक 47 जवान हुए शहीद और इतने ही घायल

जगदलपुर,(**आरएनएस**)। नक्सलियों द्वारा जवानों के लिए सुरक्षित माइन प्रोक्टेड व्हीकल मानी जाने वाली वाहन में विस्फोट कर दस घटनाओं में 47 जवानों को शहीद किया है और करीब इतने ही इन घटनाओं में घायल हुए हैं। इस संबंध में आईजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि बस्तर में जो एमपीवी वाहन चल रहे हैं वे 22 किलो तक विस्फोटक से किये गये विस्फोट को सह सकती है। इससे अधिक विस्फोटक होने पर वाहन को तो नुकसान होता ही है, साथ ही इसमें बैठे जवानों को भी क्षति पहुंचती है। उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह सुकमा के पास एमपीवी वाहन को नक्सलियों ने विस्फोट कर 9 जवानों को हताहत किया था। यह विस्फोट इतना अधिक शक्तिशाली था कि इससे एमपीवी वाहन के परखच्चे ही उड़ गये। जब यह वाहन यहां पर सुरक्षाबलों को प्रदान किया गया था, तब यह उम्मीद लगाई गई थी कि इस वाहन से नक्सलियों से लड़ने में भरपूर मदद मिलेगी। लेकिन नक्सलियों ने 22 किलो से ऊपर विस्फोटकों से विस्फोट कर पिछली दस वारदातों में सुरक्षाबलों को भारी नुकसान पहुंचाया। एमपीवी को उड़ाने की पहली घटना वर्ष 2005 में नारायणपुर जिले के अंतर्गत फरसगांव और दंण्डवन के बीच हुई थी। इसमें सवार सुरक्षाबलों को 18 जवान घायल हुये थे। इसके बाद सुरक्षाबलों ने इस वाहन के बारे में नये सिरे से सोच कर नई रणनीति बनाने की पहल की और इस वाहन को सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत सतर्कता के साथ चलाया। लेकिन नक्सलियों ने सुरक्षाबलों की इस रणनीति को भी भेद कर दिया। सर्वाधिक परेशानी इन वाहनों के विस्फोटकों के विस्फोट को सहने से हुई तथा वाहनों की विस्फोट सहने की क्षमता कम रहने से वारदातें घटित हुई। जिस पर अब पुनर्विचार की आवश्यकता है और नक्सलियों से लड़ने के लिए नई रणनीति की जरूरत है।

नक्सलियों ने आंबा कार्यकर्ताओं की मांगों को जायज ठहराया

दंतेवाड़ा,(**आरएनएस**)। माओवादियों ने एस्सार स्टील के पस पर्चे फेंके है। यह पर्चे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में है। माओवादियों ने पर्चो में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 18 हजार रूपए व सहायिकाओं को 10 हजार रूपये देने सेवा समाप्ति परक कार्यकर्ताओं को तीन लाख व सहायिकाओं को 2 लाख रूपए देने की बात लिखी है। साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग भी रखी है। माओवादियों ने पर्चो के माध्यम से बेंगपाल में हुई मुठभेड़ को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि बेट्टी भीमा को फर्जी मुठभेड़ कर मारा गया। 13 वर्षीय मड़काम सोम्बरू की हत्या की न्यायिक जांच कर दोषियों को दण्ड दिया जाए।